

**Participants : [Rawat Prof. Rasa Singh](#)**

an>

Title: Need to supply better quality of wheat through PDS in Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष जी, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानों से जो गेहूं बेचा जा रहा है वह खाने के लायक नहीं है। उससे बनी रोटी में कोई स्वाद नहीं है। यही गेहूं एफसीआई के माध्यम से मिड-डे-मील, काम के बदले अनाज योजना और अकाल राहत कार्यों में दिया जा रहा है। इससे लोगों में बड़ा असंतोह है। देश के अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि यह सड़ा-गला तत्वहीन गेहूं भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से आयात किया है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि इस गेहूं को राज्यों में भेजने से पहले, भली प्रकार से, इसकी वैज्ञानिक जांच कराई जाए कि यह स्वास्थ्यप्रद है या नहीं। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों द्वारा मांगी गयी मात्रा के अनुरूप पूरा गेहूं दिया जाए। कुछ समय पूर्व बीपीएल और एपीएल से मिलने वाले गेहूं में भी पर्याप्त कटौती कर दी गयी है। अब बाजार में महंगाई होने के कारण सस्ते अनाज की दुकानों से ही लोग गेहूं खरीदना चाहते हैं। इसलिए मेरी विनती है कि पूरी मात्रा में सबको स्वच्छ अनाज मिले, इस ओर सरकार पूरा ध्यान दे। [r19]